[श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला]

एक मिडिल क्लास वाले को रख दिया जाय। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि एक आदमी हेण्डलूम लगा कर बैठा हुआ है, या पावरलूम लगा कर बैठा हुआ है, उसके पास पूंजी नहीं है। वह माल लेता है और बना कर बेचता है तो ऐसे आदमी को भी आप मेन्युफेक्चरर मान कर चलेंगे।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Do not repeat the points.

श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : मेरा आप से निवेदन यह है कि ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को पहले भी तंग किया जाता रहा है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोगों को क्या मेन्युफेक्चरर की परिधि में रखा जा सकता है या नहीं? इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है।

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please resume your seat.

श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाने वाले हैं तो इसको लाने की आपको क्या जरूरत पड़ी?

MR. CHAIRMAN: The Minister will reply to the debate tomorrow.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Eighteenth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, I beg to present the Eighteenth Report of the Business Advisory Committee.

---

18 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Loss in National Textile Corporation

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the Half-an-Hour Discussion by Dr. Laxminarayan Pandeya.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदया, प्रश्न क्रमांक 606, दिनांक 5 अप्रैल, 1978 के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि केवल मध्य प्रदेश की ही सात मिलों में प्रति मास होने वाला घाटा लगभग 48 लाख रुपया है और इसीसे यह बात सिद्ध होती है कि एन० टी० सी० के कार्य संचालन में कहीं न कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी है और उसको ठीक किया जाना आवश्यक है। यद्यपि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह बताया था कि इन घाटों को दूर करने के लिए, मिलों के आधुनिकीकरण करने, पुरानी मशीनों को ठीक करने, एक्सेस लेबर को हटाने, या उसकी संख्या कम करने तथा कुछ अन्य कदम उठा कर इस घाटे को नफे में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि मंत्री महोदय के इस विचार के बावजूद भी वहां के जो अधिकारी हैं, जिन के हाथ में कार्य सौंपा गया है वे मंत्री जी विचार कार्यरूप में परिणत नहीं कर रहे हैं और यह जो घाटा संभवतः निरन्तर बढ़ता ही चला जाएगा। उन्होंने करीब अड़तालीस लाख का घाटा प्रति मास बताया है परन्तु यह घाटा मेरी जानकारी के अनुसार 70–80 लाख प्रति-मास और सात आठ करोड़ रुपये वार्षिक का केवल मध्य प्रदेश में ही है। जिस प्रकार की कार्यप्रणाली मध्य प्रदेश के इन मिलों के अधिकारियों ने अपनाई है—नाम मैं किसी

का लेना नहीं चाहता हूं—वह ठीक नहीं है और न ही वे ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भी मध्य प्रदेश की कई मिलों में लाखों मीटर खुला कपड़ा ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी गांठे नहीं बनाई गई हैं। वह खराब हो रहा है, सड़ रहा है। इस प्रकार कपड़ा पड़े रहने के क्या कारण हैं। और यदि इस तरह की चीजों को देखा न जाए तो कैसे आप आशा कर सकते हैं कि सरकार द्वारा हाथ में ली गई इन मिलों से किस प्रकार का लाभ होगा। क्या इससे कोई घाटा कम होने की आशा कर सकता है ?

एन टी सी का गठन इस आशा से किया गया था कि जो हमारी रुग्ण मिलें या बीमार मिलें हैं उन्हें सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद, उनकी मशीनरी का आधुनिकीकरण होगा, प्रबन्ध व्यवस्था अच्छी होगी और इससे आम लोगों को लाभ होगा, कि आम लोगों को लाभ मैं समझता हूं नहीं हो रहा है उससे कुछ खास लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्हीं मिलों के द्वारा उत्पादित कपड़ा भी महंगा है जो आम लोगों को मिल रहा है। इन मिलों में भारी गड़बड़ी घोटाले चल रहे हैं। इस परिणाम के लिये इन मिलों को हाथ में नहीं लिया गया। प्रारंभ में थोड़ी सी मिलें हाथ में ली गयी थीं। बाद में उनकी संख्या 103 हो गई थी। अभी मंत्री महोदय ने कुछ दिन पूर्व बताया था स्वदेशी मिल ग्रुप के बारे में कि उसकी मिलों को हाथ में ले लिया गया है। इस प्रकार से कुल मिलें जो हाथ में ली गई हैं वे शायद 111 हो गई हैं। व्यवस्था की दृष्टि से उनको नौ सबसिडियरीज में बांटा गया है। इन की पूंजी करोड़ों की है। इसके बावजूद इन मिलों को जिस प्रकार से लाभ प्रदर्शित करना चाहिए नहीं कर रही हैं। इसका क्या कारण है मध्य प्रदेश में ? वहां के जो प्रबन्धक या व्यवस्थापक जो भी हैं उन्होंने किसी एक व्यक्ति विशेष को, मैसर्स आर जी वुड बम्बई को ईरान को निर्यात करने के लिए 14 लाख मीटर कपड़ा दो रुपये बीस पैसे प्रति मीटर की दर से तथा एक्सपोर्ट इंसैंटिव मिलाकर के 2 रुपया 75 पैसा प्रति मीटर की दर से उस को दिया गया। लेकिन इसके विपरीत लोकल मार्किट में उसी कपड़े का दाम 3 रुपये 20 पैसे या तीन रुपये 25 पैसे प्रति मीटर था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकल मार्किट की चिन्ता नहीं की गई। लोकल मार्किट में ज्यादा कीमत मिल सकती थी लेकिन उसकी चिन्ता न करना एक विचाराधीन विषय है क्योंकि लोकल मार्किट में इस कपड़े की आवश्यकता थी। सस्ते दाम का कपड़ा बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहा है क्या हमने कभी गम्भीरता से विचार किया है कि हमको अपनी दैनिक या वार्षिक प्रति व्यक्ति की आवश्यकताएं कपड़े के बारे में क्या हैं। जितने कपड़े की आवश्यकता है क्या उसकी पूर्ति करना वस्त्र उद्योग की नीति का एक अंग नहीं होना चाहिये ? पिछली सरकार के चाहे जो दोष रहे हों लेकिन हम को तो उन दोषों को ठीक कर देना चाहिए था। वस्त्र उद्योग नीति वार्षिक उत्पादन व खपत, घरेलू खपत व निर्यात आदि को मिला करके निर्धारित की जानी चाहिये थी। इन बातों को ध्यान में रख कर नीति बनाई जानी चाहिये थी कि कितने कपड़े की हमारी अपनी आवश्यकता हो सकती है। हमारा उत्पादन क्या है ? कौन सी क्वालिटी का कितना कपड़ा चाहिये आदि। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पिछले दिनों में प्रति व्यक्ति जितने कपड़े की वार्षिक खपत हमारे देश में होती है वह घट गई है ? मेरी जानकारी है कि वह घटी है। एन०टी०सी० द्वारा 111 यूनिट्स को अपने हाथ में लेने के बावजूद यदि वह घटती है तो यह हमारे लिए चिन्ता और आश्चर्य का ही विषय हो सकता है। एन० टी०सी० की राजस्थान सबसीडियरी के सम्बन्ध में कुछ तथ्य मुझे मिले हैं, मैं उन्हें भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। नवजीवन संघ राजस्थान प्रदेश से एक पत्र मिला है

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। शीर्षक यह दिया है—

एन टी सी के व्यावर मिलों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर

श्री खण्डेलवाल द्वारा खुली जांच की चुनौती

राजस्थान प्रदेश नवजीवन संघ के महामंत्री श्री प्रतापभानु खण्डेलवाल ने जिन्होंने गत अनेक वर्षों में एन टी सी में व्याप्त लाखों रुपयों के घोटाले के अनेक मामलों की जांच सतर्कता अधिकारी तथा सी बी आई द्वारा सिद्ध कराई है—और अभी भी अनेक मामले प्रकाश में लाए हैं इससे बौखलाकर भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने प्रभाव व साधनों का दुरुपयोग कर सुनियोजित ढंग से उनके चरित्र हनन की कोशिश की है और उनकी फर्म प्रभात टैक्सटाइल स्टोर्स जो उनकी आजीविका का साधन है, पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उन्होंने मिल अधिकारियों को चुनौती दी है और सरकार से मांग की है कि उन पर लगाए आरोपों की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच सी बी आई अथवा सतर्कता अधिकारियों से कराई जाए।

आगे चल कर उन्होंने लिखा है :

जिन मुद्दों की उन्होंने शिकायत की है उनकी जांच की जा कर दोषी अधिकारियों को कठोरतम दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता का चरित्र हनन न कर सके।

उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास भ्रष्टाचार के अकाट्य प्रमाण व फोटो स्टेट कापी मौजूद हैं जिससे ये लोग बौखला उठे हैं। व्यावर की महालक्ष्मी और एडवर्ड मिलों में एक मिल के 80 स्पिनिंग रिंग फ्रेम के नवीनीकरण हेतु 1 लाख रु० प्रति रिंग फ्रेम के हिसाब से ठेका दिया गया और इस ठेके के अन्दर कोटेशन लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी गयी। इस से मेरे ख्याल से लाखों रु० की हानि एन० टी० सी० को हुई है।

एक और तथ्य मध्य प्रदेश के बारे में रखना चाहता हूं सम्भवतः मंत्री महोदय की जानकारी में होगा कि इन्दौर में एन० टी० सी० के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर मार्केटिंग व पार्टी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में जो 8 लाख मीटर कपड़े का सौदा हुआ वह 2.06 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से हुआ जब कि लोकल मार्केट में उस कपड़े का भाव 2.60 पैसे था। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बावजूद मेसर्स काशीराम टैक्सटाइल्स, अहमदाबाद को कपड़ा बेचा गया। इस प्रकार से एन० टी० सी० को घाटा हुआ क्योंकि यह सौदा बाजार भाव से सस्ते दाम पर हुआ।

इसी प्रकार एक और उदाहरण है, जो हमारे एन०टी०सी० के ऐक्सपोर्ट ऐडवाइजर हैं उनके विरोध के बावजूद मेसर्स आर० जे० वुड कम्पनी के साथ सौदा हुआ जिसमें 4, 5 लाख रु० की हानि हुई। किन अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ, कौन कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं यह मंत्री महोदय मालूम करें। एक तरफ 4, 5 लाख रु० की हानि, दूसरी तरफ़ स्पिनिंग रिंग के ठेके दिये जाने में 10 लाख रु० या इससे अधिक की हानि और इसके अलावा प्रति मास 50 लाख रु० की मध्य प्रदेश के मिलों में हो रही हानि, विचार का विषय है। चाहे वह राजस्थान की यूनिट हो या मध्य प्रदेश की हो, अगर इस तरह से काम होगा तो अपने आप एन०टी०सी० को घाटा होगा और वह कभी भी मुनाफ़ा नहीं कमा सकती। बंगाल में एन० टी० सी० का क्या हो रहा है।

मैं एक न्यूज आइटम की तरफ़ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"National Textiles Move Resented".

यह पत्र कलकत्ता का है, जिसमें लिखा है कि

बंगाल की सरकार ने चेयरमैन की नियुक्ति पर आपत्ति की है । वहां की सरकार के साथ कुछ हमारा तालमेल नहीं रहा है या वहां क्यों इस प्रकार की गड़बड़ी है उसको मंत्री महोदय देखेंगे :

पत्र में कहा गया है—

"The National Textile Corporation's appointment of a new chairman for its eastern subsidiary, with headquarters in Calcutta without consulting the West Bengal Government was questioned in Writers' Buildings on Tuesday. Mr. Kanailal Bhattacharyya West Bengal's Industries Minister, has requested the Union Minister, Mr. George Fernandes to intervene in the matter.

The subsidiary's chairman, Mr. C. Guha Mazumdar, an IAS Officer of the West Bengal cadre, was asked by the new incumbent, Mr. S. Sain, to handover charge on Tuesday morning."

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आर्डर की कमप्लायेंस हुई कि नहीं । साथ ही में यह भी जानना चाहूंगा कि मौडर्नाइजेशन के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा हुआ है उससे कितनी मिलें सुधरी हैं । आगे की प्रक्रिया क्या है या कार्यक्रम क्या है । लगभग 117 करोड़ रु० कुल मिलाकर जो घाटा सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शित किया गया है, उसमें से 106 करोड़ की हमको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, और अभी भी 11 करोड़ का घाटा है । उसको तो पूरा करने का प्रत्यन करेंगे, लेकिन किस प्रकार प्रयत्न करेंगे ? और अगर ऐसे ही रहा कि प्रबन्ध अधिकारी या प्रबन्धक या दूसरे अधिकारी, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, हो, वह इसी प्रकार लाखों मीटर कपड़ा सड़ायेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ सौदा करेंगे, ठेके देने में अनियमितता करेंगे, माल कम दाम पर बेचेंगे और ऐक्सपोर्ट में घाटा देंगे तो मैं समझता हूं कि एन० टी० सी० कभी भी लाभदायक कौरपोरेशन नहीं बन सकती । यह एक गंभीर मामला है और पूरी चिंता व सतर्कता की आवश्यकता है ।

यद्यपि मेरे पास बहुत सी जानकारी है लेकिन समयाभाव के कारण सब में विस्तार से नहीं जा सकता, उनके बारे में मंत्री महोदय को लिख कर भेज दूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि जो बातें मैंने बतायी हैं उन सब के बारे में किन किन पार्टीज़ के साथ सौदा हुआ ? सौदों में अनियमितताएं क्यों हुई ? कौन कौन लोग दोषी है, क्या कारण थे कि ऐक्सपोर्ट ऐडवाइज़र के विरोध के बावजूद भी सौदा किया क्या कारण था कपड़े का सौदा किया और कपड़े की डिलिवरी बाहर देनी थी और हमारा कपड़ा वापस लौट कर आया, उदाहरण के लिये मेसर्स राज लक्ष्मी को 30 लाख रु० का कपड़ा भेजा था वह पूरा का पूरा वापस आया जिसमें 50,000 रु० का हमको डैमरेज देना पड़ा, इन तमाम लैप्सेज़ के बारे में मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें ताकि एन० टी० सी० जिसमें हमारी करोड़ों रु० की पूंजी लगी हुई है, वह एक लाभप्रद संस्था के रूप में उभर कर हमारे सामने आये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को वस्त्र उद्योग के संबंध में एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए, जिससे प्राइवेट मिलों, पावरलूम और हैंडलूम के साथ हितों का टकराव न हो और कारपोरेशन में दक्षता पैदा हो । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि दक्ष अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाये और जो अदक्ष और भ्रष्ट अधिकारी जो जान-बूझ कर मिलों को घाटे में ले जा रहे हैं उन्हें हटाया जाये, क्योंकि उन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें हटा कर अच्छे प्रबन्ध के लिए अच्छे लोगों को नियुक्त किया जाये । और अन्त में पुनः आग्रह करूंगा कि

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

मध्य प्रदेश की एन० टी० सी० द्वारा संचालित मिलों को जिनमें विशेषकर बरहानपुर, मिल, बरहानपुर, कल्याण मिल, इन्दौर और हीरा मिल, उज्जैन आदि इकाइयों को ठीक करेंगे ताकि मिलें बन्द होने की हालत में न पहुंचें। साथ ही राजस्थान की महालक्ष्मी तथा एडवर्ड मिलों को जो घाटे में हैं नफे में परिवर्तित करने हेतु योग्य कदम उठावेंगे, ताकि जनता सरकार की इस नीति को कार्यान्वित किया जा सके कि देश के आम आदमियों के उपयोग के लिए सस्ते दामों पर अच्छा कपड़ा सुलभ किया जाये।

मुझे आशा है कि मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, मंत्री महोदय उन पर प्रकाश डालेंगे, और जो तथ्य मैंने रखे हैं, वह उनके आधार पर जांच की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। मैं इस बारे में कुछ और सामग्री उन्हें भिजवाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी एन० टी० सी० के कार्यकरण पर पूरी तरह विचार करेंगे और उसे एक स्वस्थ स्वरूप प्रदान करेंगे।

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): On the losses in NTC I want to put a question with regard to the subsidiary of the National Textile Corporation to which a reference has already been made by Dr Laxminarayan Pandeya, Now there is a great confusion prevailing in the National Textile Corporation for its eastern subsidiary. Its present Chairman, Shri C. R. Guha Majumdar has been there for some time, about two or three years and serious charges of corruption have been levelled against him. He has made a certain arbitary appointment; he has appointed one ex-actress as the Public Relations Officer and under him the losses in the eastern subsidiary have gone up to Rs. 80 lakhs per month. The whole Corporation is now very badly managed.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI SAUGATA ROY: My simple question is that now this particular Chairman has done a very bad thing.

MR. CHAIRMAN: This is not a question. Please confine yourself to the question.

SHRI SAUGATA ROY: I will confine myself to the question. Whether the Minister (a) is aware that this Chairman of the National Textile Corporation has opened four showrooms in the constituency of one particular M.P. belonging to the Ruling Party in West Bengal and whether the inauguration of such show-rooms has been advertised at NTC's cost widely in the West Bengal papers; and (b) whether the Minister is aware that the West Bengal even after the Central Government sent a particular officer to be the Chairman of the National Textile Corporation to take over from Mr C. R. Guha Majumdar he has prevented that officer from acting as the Chairman of the National Textile Corporation If so, what steps the Minister proposes to take with regard to the Chairman of the Eastern Subsidiary Corporation?

MR. CHAIRMAN: Prof. Mavalankar, I would remind you to put questions only.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Madam Chairman, the state of affairs with regard to the working of NTC is so much away from being satisfactory or encouraging that if you really confine us/asking questions not only we will ask questions but perhaps the Minister will beg and say that he will also ask questions but not give answers! That is the whole state of affairs unfortunately. There are 103 sick units and perhaps two or more are added. Now there are 105 or more sick units. I know that the policy of the Government is not to add more units to this. But my question is what is the Government doing in regard to seeing that

the NTC itself does not become sick? I believe and therefore say that NTC is already anaemic in terms of its working and conditions. If it goes like this, then the units which are to make everybody healthy if they are sick themselves how will the things improve? What is the Government doing with regard to making NTC less anaemic and more energetic and more dynamic? (2) With regard to the Chairman of NTC, I am not against the IAS Officers as such. But I do not like IAS Officers as of right to become the Chairman of various bodies thinking that because of their being in the IAS cadre, they know everything about a particular thing. Therefore my second question is: why is it that the Chairman must, of necessity, be an IAS person? Should not a public sector undertaking like the NTC have, as Chairman a person who is experienced in textiles drawn from a city like Ahmedabad or Bombay or Coimbatore wherever such qualified persons are available. I do not want to go in detail. The past experience of an ex-Chairman, unfortunately, has not been a happy one. The past Chairman had to go away in distress. Therefore please do something with regard to this. My question is what are you doing with regard to the appointment of Chairman and other members. Part (c) of my question is this. With regard to the management of the NTC mills, so that they do not go into heavy losses, will not Government think in terms of having a special kind of trained cadre—so that the same old management which was running the units earlier do not come again?

Then, Madam Chairman why are they forced to produce only controlled cloth and why do they not go in for quality cloth?

If those four questions are answered, perhaps, he will have given us some satisfactory reply about making NTC a more energetic and more dynamic body.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): The half-an-hour discussion has arisen on the NTC subsidiary in Madhya Pradesh. While raising the discussion Dr. Pandeya had this to say:

घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है ।

यह बात सही नहीं है । घाटा निरन्तर घटता जा रहा है । 75–76 में घाटा रहा 8 करोड़ 25 लाख रुपया, 76–77 में घाटा रहा 7 करोड़ 68 लाख रुपया और उसी के साथ अगर उस साल का जो बोनस बाद में दिया गया वह जोड़ा जाए तो 93 लाख रुपये को और जोड़ना पड़ेगा, यानी लगभग 8 करोड़ 60 लाख रुपये । 77–78 में जिस साल को लेकर यह प्रश्न था, जिस प्रश्न को लेकर यह बहस अभी है, घाटा आया है 5 करोड़ 11 लाख, 8 करोड़ 25 लाख, 7 करोड़ 68 लाख और 5 करोड़ 11 लाख ।

जब यह प्रश्न पूछा गया था अप्रैल महीने में, उस प्रश्न का जवाब देते समय जो जानकारी हमारे पास थी अप्रैल 77 से जनवरी 78 तक की, उसमें हमने यह बताया था कि घाटा उन दस महीनों में हुआ है 4 करोड और लगभग 80 लाख । 4 करोड़, 79 लाख 96 हजार या यानी लगभग 4 करोड़ 80 लाख और इसलिए कहा गया था कि औसतन की महीना 48 लाख रुपये का घाटा है । उसके बाद फरवरी और मार्च महीने में घाटा और कम हो गया, स्थिति में और सुधार हो गया और अभी जो मेरे पास जानकारी है उस के अनुसार पूरे साल में औसतन की महीने जो घाटा हुआ वह 42 लाख रुपये हुआ । इसलिए यह निरन्तर बढ़ता नहीं जा रहा है, निरंतर घटता जा रहा है ।

कारण क्या है ? कारण कई हैं ।

एक बात तो हम सभी जानते हैं कि यह पुरानी मिलें थीं और घाटे में चलने वाली मिलें थी जिनको लिया गया था । इन में से कुछ मिलों की स्थिति सुधर गई है और

[श्री जार्ज फरनान्डीज़]

और कुछ की स्थिति अभी भी जैसी सुधरनी चाहिए वैसी नहीं सुधरी है । बहुत पुरानी मशीनरी और सारा पुराना झमेला जो घाटे में चलता था उसको साल भर में सुधारना सम्भव नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसा मैंने बताया, वह सुधर रही हैं ।

दूसरा कारण यह है कि जिस तरह का कपड़ा इसमे बनता था उस कपड़े में भी कुछ कमियां रहीं जिसके चलते जिस प्रकार की मार्केट होनी चाहिए थी वह मार्केट नहीं रही । डा० पांडेय का कहना ठीक है कि इस समय भी काफी कपडा मिलों के पास पड़ा हुआ है । 31 मार्च, 1978 को जो कुल कपड़ा पड़ा हुआ था वह 7 करोड़ 70 लाख रुपये का था । । अब यूं तो कुछ स्टाक रहता है, जैसे ही कपड़ा बना वैसे ही बाहर नहीं जायेगा और इन मिलों के बारे में जो हिसाब लगाया है उसके चलते अंदाज यह है कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए तक का कपड़ा मिलों में रहने की बात मानी जा सकती है लेकिन इस समय 3 करोड का अधिक कपडा मिलों के पास पड़ा हुआ है । इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गये हैं । अभी कुछ दिन पहले तक मध्य प्रदेश की जितनी एन टी सी की मिलें थीं उनका कपड़ा बेचने का काम स्वयं मिलें खुद ही करती थीं लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश की एन टी सी मिलों की जो सब्सीडियरी यूनिट है उस ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया है और कपड़ा बेचने की जो सारी व्यवस्था है उसमें कई लोग कई अफसर इस काम को संगठित रूप से कर रहे हैं जिसके चलते मिलों के बीच आपस में कांपिटीशन न हो और जिसमें किसी का माल तो बिक जाये और किसी का न बिके । सभी मिलों का माल एक साथ बेचने का इंतजाम अब हो चुका है और मुझे विश्वास है कि जो स्टाक पड़ा हुआ है उसको बाहर भेजने में अब हमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ।

एक कारण और भी है कि इन मिलों में श्रमिकों की संख्या कुछ अधिक है । यह बात सभी लोगों ने मानी है, हमने तो मानी ही है, राज्य सरकार ने भी मानी है, मिलों के संचालकों ने भी मानी है और मजदूर सगठनों ने भी मानी है और कुछ समझौता भी हो गया था कि इसके बारे ; क्या किया जाय लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थिति वहां पर बन गई कि मजदूर सगठन चलाने वाले लोगो में जो समझौता हो गया था उसको एकतारफा उन लोगो ने तोड़ डाला और यहां तक तोड डाला कि जितने मजदूर पहले से ज्यादा थे उनके अलावा और अधिक भर्ती करने की स्थिति वहां पर लाई गई आज वहा पर इन मिलो में मैं समझता हू प्रति माह 25 लाख रुपए अधिक तनख्वा देनी पड़ती है उन लोगो को जिनकी जरूरत मिल चलाने में नही है । इस बारे में हम राज्य सरकार से काफी कहते रहे हैं कि आप कुछ मदद करे, मजदूर सगठनों से भी कहते रहे हैं कि आप कम से कम कुछ करिए लेकिन अभी तक जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिला है । स्थिति यह है कि की माह 25 लाख रुपया जो देने की जरूरत नही है, जो बाहर नहीं जाना चाहिए वह उन लोगो को तनख्वाह देने में खर्च करना पड़ रहा है । यह काफी पैसा है अब फी माह 42 लाख का नुकसान हो रहा है उसमें 25 लाख रुपया सिर्फ इस तरह से तनख्वाह देने है जा रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है । इस में किसी को मदद करनी चाहिए, हम चाहेंगे कि संबंधित मजदूर संगठन और राज्य सरकार, दोनों मिलकर हमें मदद करेंगे ताकि इस घाटे वाली स्थिति को सुधारने में हमें ज्यादा समय न लगे । अब मिलों के आधुनिकीकरण वाली बात बहुत तेजी से चल रही है ।

एक सवाल आप की ओर से पूछा गया और प्रो० मावलकर की ओर से भी पूछा गया

कि एन० टी० सी० की मिलों की हालत को सुधारने के लिये हम क्या कर रहे है ? एन० टी० सी० की 103 मिलों के सुधार और आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है, जिस पर 203 करोड रुपया खर्च होगा । इस में से कुछ रुपया खर्च हो चुका है और कुछ खर्च हो रहा है । मध्य प्रदेश के जो यूनिटस है—इन के आधुनिकीकरण के लिये कुल मिला कर 14 करोड 40 लाख रुपया हमें खर्च करना है, जिसमें से 4 करोड 90 लाख रुपया खर्च हो चुका है, 1 करोड इस समय खर्च हो रहा है और साल-भर मे 1 करोड 81 लाख रुपया और खर्च होना हैं । जैसा मैंने अभी बतलाया था—देश भर की 103 मिलो के लिये 203 करोड रुपया खर्च किया जाना हैं, इस से मुझे विश्वास है—जैसे-जैसे आधुनिकीकरण का काम होता जायगा, एन० टी० सी० की अधिकांश मिलों को मुनाफे की ओर ले जाने में हमें कामयाबी मिलेगी ।

जैसा मैंने पहले भी इस सदन में एन० टी० सी० के बारे में चर्चा करते हुए कहा है—जहां दिसम्बर, 1976 में कुल मिलाकर 17 मिल मुनाफे में चल रही थीं, वहा दिसम्बर, 1977 में 46 मिलें मुनाफे में चलने लगी है । उनमें प्रतिदिन निरन्तर सुधार होता जा रहा है, कहीं भी कोई बिगाड़ नही हो रहा है—इस लिये इस में कुछ समय लग जायगा । जो स्थिति आज मैं देख रहा हू, उस को देखते हुए मै निश्चित रूप से कह सकता हू कि एन० टी० सी० सुधार की ओर जा रही है, बिगाड़ की ओर नहीं जा रही है ।

डा० पाण्डेय ने इस समय कुछ ऐसे मसले छेड़े हैं—बम्बई की कुछ कम्पनियों, मध्य प्रदेश की कुछ कम्पनियों या निर्यात के किसी मामले में कुछ गलत व्यवहार हुआ है । इस के बारे में हम को जांच करनी पड़ेगी क्योंकि आपने इन के बारे में हम को अभी जानकारी दी है । मैं तत्काल इन पर कुछ नहीं कह सकता हूँ लेकिन जो बातें भी आप ने कही हैं, या कोई और मसले भी जो आप देना चाहें, देवें, मैं उन सब पर जांच कराऊगा और यदि कोई गलत काम हुआ है, या कोई गलत व्यवहार किसी अफसर से हुआ है, तो उसको दुरुस्त करूगा और उनको सजा देने का काम भी किया जायगा, कोई गलत काम करने पर किसी को मुफ्त में छोड़ा नहीं जायगा ।

आपने दो बातो के बारे मे इशारा किया—एक राजस्थान की बियावर मिल के बारे में और दूसरे-पश्चिमी बंगाल की मिल के बारे में, जिसका जिक्र हमारे मित्र सौगत राय ने किया है । बियावर मिल के बारे में हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसकी इस समय जाच हो रही है और जैसे ही उस की रिपोर्ट आ जायेगी, उस पर जो भी कार्यवाही की जानी चाहिये, वह की जायगी । पश्चिमी बंगाल का मामला थोड़ा पेचीदा है । मुझ को अभी जानकारी मिली है कि जब कोई अफसर वहा पर भेजा गया तो वहां गुहा मजूमदार ने शायद चार्ज-हैण्डओवर हैं करने से इन्कार किया इस की हम तत्काल जांच करायेंगे और जो भी कार्यवाही करनी है, जो भी कदम उठाने है, वे उठाये जावेंगे । लेकिन जो पेचीदा सवाल है—वह हैण्ड-ओवर करना या न करना नहीं है । यह सही नही है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार से सलाह-मशविरा नहीं हुआ है या पश्चिमी बंगाल सरकार के कहने के विपरीत कोई बात हुई है । हमें मुख्य मंत्री जी की ओर से चिट्ठी आई थी, उद्योग मंत्री जी की ओर से चिट्ठी आई थी, वहां सब्सीडियरी का चेयरमैन कौन बने, इस के बारे में भी बातें हुई हैं । जो चेयरमैन थे, उनके बारे में शिकायतें भी है—यह भी दुरुस्त है । उसमें कोई एक्ट्रेस है—ऐसी शिकायत भी हो सकती है, लेकिन एक्ट्रेस होने से कोई पब्लिक-रिलेशन आफिसर नही हो सकता है—मैं समझता हूं सौगत राय जी को ऐसी शिकायत नहीं है ।

that an actress is not qualified to become a public relations officer.

MR. CHAIRMAN: In fact, very well qualified.

PROF P. G. MAVALANKAR: Yes, she would be a better public relations officer.

श्री जार्ज फरनान्डीज हमारे सौगत राय जी नौजवान आदमी हैं—उन को ऐसा नही कहना चाहिये—वह यहां पर बोल कर चले गये, इस समय मौजूद नही है। मैं समझता हू कि यह बात बहुत महत्व की नही है। लेकिन कुछ और मसले हैं—पश्चिमी बगाल मे जो हमारी सब्सीडियरी है उसको चलाने के बारे मे काफी शिकायतें है, जिनके बारे मे जांच हो रही है, कुछ हो चुकी है और जो नया अफसर वहा पर नियुक्त करना है, उस के बारे मे इस समय कुछ कदम उठा रहे है। इसी दरमियान गुहा मजुमदार को रिप्लेस करने के लिए कोई अफसर गये थे और जो घटना हुई हो, उस पर जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह कार्यवाही हम करेंगे।

MR CHAIRMAN Kindly be brief.

श्री जार्ज फरनान्डीज . मैं अभी समाप्त कर रहा हू।

इस मे एक प्रश्न एन० टी०सी० को पूरी तौर पर सुधारने के बारे मे भी था। इस स्थिति को काबू मे लाने के बारे मे हम क्या कर रहे हैं, यह मैं आप को बता दू कि पूरे टैक्सटाइल्स के बारे मे एक नई नीति करीब करीब तैयार कर चुके हैं और हमारा प्रयास यह रहेगा कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले संसद् के सामने उसे पेश किया जाए और प्रो० मावलंकर ने जो भी सवाल छेड़े हैं, नीति निर्धारण के रूप मे उनको भी उस में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर भी कुछ लोगों को उस में शिकायत हो और नीति को कुछ लोग स्वीकार करने में गुरेज करें लेकिन बुनियादी तौर से हम लोगों की कपड़े के बारे में जो नीति रहेगी, वह यह रहेगी कि देश के लोगों को सस्ते दामों पर अच्छा कपड़ा मिले और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो दूसरी चीजें हैं वे बेफायदे हैं। यह एक बुनियादी बात है और इस बुनियादी बात को मद्देनजर रखते हुए हम एक नीति बना रहे हैं। उसमे एन० टी० सी० को एक विशेष स्थान, एक विशेष काम हम देना चाहते हैं और अन्य मिलों की जो उन की अपनी शिकायतें हैं या उनकी अपनी बातें है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी को भी कोई शिकायत न रहे, ऐसा हम लोगो की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और ऐसा प्रयास करने के बाद हम जो नीति बना रहे हैं, वह करीब करीब पूरी बना चुके हैं और इस सत्र के समाप्त होने से पहले हम उसे सदन के सामने पेश करने का प्रयास करेंगे।

आप ने ट्रेन्ड केडर और आई० ए० एस० को ही चैयरमेन बनाने की बात छेड़ी है, इसमे दो मत नहीं हैं और मैं भी यह मानता हू कि ऐसी बात नही है कि आई० ए० एस० बना हुआ आदमी ही चेयरमैन बनने के लायक है और अन्य जो लोग हैं वे नालायक हैं। मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हू कि यह जो ट्रेन्ड केडर की बात कही गई है वह हो सकती है लेकिन मैं यह कहूगा कि हमे एन० टी० सी० को पूरा-पूरा रीस्ट्रक्चर करने का काम करना है। 103 मिलें तो पहले ली हुई हैं और अभी जो ली गई हैं वे 8 हैं, एक नहीं पांच नहीं, पांच केन्द्रों पर 8 मिलें हैं जिन मे मैनी मे 3 यूनिट्स हैं इस तरह से कुल मिला कर 111 मिलें हैं और हम सम्पूर्णतया उस के संगठनात्मक उस के व्यवहारात्मक और हर दृष्टि से उसका नवीकरण करने के काम मे लगे हुए हैं और उस पर काफी विचार हो रहा है, काफी चर्चा हो रही है और मुझे विश्वास है कि हम एन० टी० सी० को एक नई दिशा देने के काम मे सफल जाएंगे लेकिन दरमियान के समय मे लोगों को सस्ते दाम पर अच्छा कपड़ा देने का जो काम करना है, उसके लिए एन० टी० सी० पर एक विशेष जिम्मेदारी हम डालेंगे। मैंने जो सवाल छेड़े गये थे,

उनका जवाब देने का काम किया है। हमारे माननीय मत सौराय जी इस समय यहां नही है। उन्होंने बंगाल मे किसी कांस्टीटुयेन्सी मे एक दुकान खोलने की बात कही थी। जो और सवाल हुए हैं उन पर हम जांच करेंगे और अभी हमारे पास इस सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही है।

धन्यवाद।

PROF. P. G. MAVALANKAR: Thank you I hope you will bring it soon.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar) Thank you, Madam.

MR CHAIRMAN· Now tht House stands adjourned till 11 a m on Tuesday the 9th May, 1978

18.33 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesda, May, 9 1978/Vaisakha 19, 1900 (Saka)

GMGIPMD—M—1124 L.S.—10-7-78—883